THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) The data on rose cultivation is not being collected as it is not a forecast crop. However, there is no report about decline of area under rose cultivation.

(b) Yes, Sir.

(c) (i) Indian Council of Agricultural Research is implementing a research scheme for improving yield and quality of rose oil;

(ii) Department of Industrial Development has approved two programmes:—

(a) M/s. All India Scheduled Caste Development Cooperative Society Limited, New Delhi; and

(b) Evergreen Bioflora Private Limited, Dharmapuri, Tamil Nadu.

(iii) Government of India have liberalised the import policy for import of planting material including roses;

(iv) The National Horticulture Board have implemented a scheme for development of floriculture, particularly, roses in Sikanderpur, District Ballia (UP) at a total cost of Rs. 11.66 lakh. The scheme is being implemented since 1991 for a period of 3 years on 50:50 basis to be shared by State Government of Uttar Pradesh and National Horticulture Board.

खाद्यान्नों के बीज

1651. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बोये जाने वाले खाद्यान्नों के कौन-कौन से बीज विदेशों में पेटेन्ट किये गये हैं;

(ख) डुंकेल प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत में वैकल्पिक बीजों का विकास किया गया है अथवा किया जायेगा; और

(ग) भारत में खाद्यान्नों के कौन-कौन से बीजों को पेटेंट किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) बीजों के लिये भारत में कोई पेटेन्ट कानून नहीं है। भारतीय कानून के अन्तर्गत बीजों के मामले में विदेशों के पेटेन्टस संरक्षित नहीं हैं। इसलिये किसी संभव विदेशी पेटेन्ट के बारे में सूचना एकत्र करना भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है।

(ख) डुंकेल प्रस्तावों के होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की 1900 से अधिक किस्में/सकर किस्में निर्मुक्त तथा अधिसूचित की गई हैं। चल रहे प्रयासों में विभिन्न फसलों की आशाजनक किस्में/सकर किस्में विकसित होने वाली हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारत में बीजों के बारे में कोई पेटेन्ट कानून नहीं है।

Starvation deaths in Tripura

1652. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether a Parliamentary team visited Tripura on 9th May, 1992, to assess the famine conditions prevailing in some parts of North Tripura District including Chwmanu Block area, where starvation deaths have taken place;

(b) whether those Parliament Members reported starvation deaths and deaths due to ailment after long-drawn starvation; and

(c) if so, the details of steps taken by Government to rush relief to Tripura?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.